" वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रयास और एस. डी.जी. की उपलब्धि " विषय पर भाषण, जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों का शिखर-सम्मेलन, जापान, 3 से 5 नवंबर 2019.

माननीय अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारीगण, देवियों और सज्जनो,

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद के प्रतिनिधि के रूप में इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण विषय – वैश्विक चुनौत्तियों के समाधान के प्रयास और एस. डी.जी. की उपलब्धि - पर जी-20 पीठासीनों के शिखर सम्मेलन में अपने विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर के लिए मैं सभापति के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

आज विश्व विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है जो कि न केवल विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रोकती हैं, बल्कि मानवता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। मैं केवल कुछ प्रमुख चुनौतियों का ही उल्लेख करूंगा।

सबसे पहली और प्रमुख चुनौती आतंकवाद है। आतंकवाद न केवल समाज को नुकसान पहुंचाता है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी गंभीर नुकसान होता है और यह मौजूदा विकास को नष्ट कर देता है।

दूसरी प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तन की है यह न केवल हमारे ग्रह का स्वरूप बदल रही है बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए गंभीर जोखिमों तथा अस्थिरता का भी सृजन कर रही है।

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समान और साझी किन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक समग्र तरीके से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मैं ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं। वैश्विक ऊर्जा के उपयोग में कुशलता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। हमें सस्ती तकनीक के विकास के लिए निवेश करना होगा।

जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापवृद्धि के प्रभावों को कम करने की हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने और आगे चलकर इसे 450 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बनाई है।

2030 एजेंडा और इसके अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य भारत की अपनी विकास प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। भारत के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों तथा **सबका साथ, सबका विकास** के एजेंडे का सतत विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य है।

विकास एजेंडे के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 'स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75' योजना आरंभ की है जोकि सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और जिसका उद्देश्य 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है।

आयुष्मान भारत, विश्व में किसी सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत 500 मिलियन भारतीयों को 7100 अमरीकी डॉलर का वार्षिक चिकित्सा कवर प्रदान किया जा रहा है।

पोषण योजना के द्वारा महिलाओ एवं बच्चो में कुपोषण समाप्त करने की महत्वपूर्ण और प्रभावकारी पहल की गई है।

युवाओं में स्वरोजगार एवं दक्षता बढ़ाने के लिए स्टार्ट अप्प इंडिया एवं स्किल इंडिया योजनाओ से लाखो युवा लाभान्वित हो रहे हैं।

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना ने कन्या शिशु के बारे में देश और समाज की सोच में क्रन्तिकारी बदलाव लाया है.

इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि जी-20 देशों का सकल घरेलु उत्पाद विश्व के कुल सकल घरेलु उत्पाद का 80 प्रतिशत और विश्व व्यापार 75 प्रतिशत से अधिक है। हमारी प्रतिबद्धता और सामूहिक प्रयास न केवल पूरे विश्व के लोगों के जीवन और उनकी आजीविका में आमूलचूल परिवर्तन लाने में बल्कि 2030 एजेंडे के लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। संसद सदस्य होने के नाते इन आकांक्षाओं को पूरा करने और 2030 एजेंडा के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वाभाविक रूप से हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

धन्यवाद।